यूपी में अब सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, सुरक्षित निवेश

सात साल में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर हुए कई अहम बदलाव, माफिया का जोर खत्म, निवेश का बना बड़ा डेस्टिनेशन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार ने बीते सात साल में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कई आमूलचूल परिवर्तन करके देश भर में मिसाल कायम की है। यूपी सरकार के मॉडल और प्रयोगों की सराहना के साथ उसे अन्य राज्य अपने यहां लागू भी कर रहे हैं। माफिया का जोर खत्म करने में सफलता मिली है तो महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने वालों को सख्त सजा दिलाई जा रही है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य भी बन चुका है, जहां धार्मिक स्थलों पर मचने वाले शोर को शांति से रोका गया है।

गौरतलब है कि यूपी पुलिस ने कई संवेदनशील मौकों पर अपनी व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया है, जिससे प्रदेश सरकार की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधरी है। राज्य सरकार ने पुलिस को खुली छूट दी, जिससे कानून-व्यवस्था बेहतर हुई और यूपी निवेश का बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। राज्य सरकार उद्यमियों का भरोसा जीतने में कामयाब रही, नतीजतन वैश्विक निवेश सम्मेलन में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए। इस भरोसे की मजबूती का अनुमान 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने से लगाया जा सकता है। वहीं, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर मंदिर निर्माण और फिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह शांतिपूर्ण तरीके से कराना मजबूत नेतृत्व और सटीक फैसले लेने की मिसाल बन चुका है।

डंडा, डाटा और एआई बनी ताकत

कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस के संसाधनों में भी इजाफा किया है। डंडा, डाटा और एआई के जरिये समाज को नुकसान पहुंचाने वाले अराजक तत्वों पर अंकुश लगाया जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा मजबूत रखने के लिए पीएसी बल को महिला शक्ति की ताकत भी दी जा रही है। मादक पदार्थों से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स केंद्र और राज्य की बाकी एजेंसियों के साथ काम कर रही है। प्रदेश में हुए कई बड़े आयोजन में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रयागराज में कुंभ की तैयारी और अयोध्या की निगरानी हो रही है।

मुश्किलों से ले रहे सबक

राज्य सरकार अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सामने आने वाली मुश्किलों से भी सबक लेकर रही है। सीएए के खिलाफ वर्ष 2019 में हुए हिंसक प्रदर्शन की चपेट में 19 जिले आए, हालांकि इस बार पूरी शांति रही। राज्य सरकार ने कई मामलों में आईपीएस अफसरों तक को नहीं बख्शा, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ पैदा हुआ। पेपर लीक के कई प्रकरण सामने आए, जिनमें सख्त कार्रवाई की गई।

देशभर में सर्वाधिक 14 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा शहर हवाई नक्शे पर आ गए हैं। सर्वाधिक हवाई अड्डों के मामलों में यूपी देशभर में नंबर वन हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य भी यूपी से पिछड़ गए। यूपी में 14 हवाई अड्डे हैं, जहां इस गर्मी में नियमित वाणिज्यिक उड़ानें मिलेंगी। हाल ही में अयोध्या, आजमगढ़, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती में हवाई अड्डों के उद्घाटन ने राज्य को देश के विमानन लिंक चार्ट में शीर्ष पर पहुंचा दिया है।

महाराष्ट्र दूसरे तो गुजरात तीसरे नंबर पर

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा शहरों की एयर कनेक्टिविटी के मामले में दूसरे नंबर पर है। वहां 11 हवाई अड्डे संचालित हैं। तीसरे नंबर पर नौ हवाई अड्डों के साथ गुजरात है। चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 8 हवाई अड्डे संचालित हैं। पांचवें पर सात हवाई अड्डों के साथ असम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 6-6 और मध्य प्रदेश व ओडिशा में 5-5 एयरपोर्ट हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब व अरुणाचल में चार-चार, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड व उत्तराखंड तीन-तीन और गोवा व जम्मू-कश्मीर दो-दो एयरपोर्ट हैं। एक हवाई अड्डे वाले राज्यों में दिल्ली (भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना (हैदराबाद), त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव और लद्दाख हैं। ब्यूरो